



अपीलार्थी के पति की खास खरीदगी भूमि अंदर मौजा-आलमनगर, थाना नं०-72/1, पुराना खाता नं०-432, पुराना खेसरा नं०-1445 रकवा-5 डी० अन्दर नया खाता नं०-831, नया खेसरा नं० 2164 एवं पुराना खाता 432, पुराना खेसरा 1445 अन्दर नया खाता 1457, नया खेसरा नं०-2165 रकवा-4 डी० चौहदी उत्तर-जगन मंडल, दक्षिण-सड़क, पुरब-निज वादी, पश्चिम-सड़क जिसके विक्रेता राधे याम राम क्रेता अपीलार्थी के स्व० पति नंददेव भार्मा हैं तथा जिसका दस्तावेज सं०-3108, वर्ष-1960 है, तथा जिसका हाल खतियान भी अपीलार्थी के पति के नाम खाता दर्ज है उसे वा जबरन कमजोर वो असहाय समझकर रेस्पोजेन्ट/प्रतिवादी अवैध तरीके से दखल कर अपीलार्थी को बेदखल कर दिया जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के पति की खास खरीदगी भूमि है। जिसका जमाबंदी अपीलार्थी के पति के नाम से कायम है वो हाल सर्वे में कागजात वो दखल के अनुरूप अपीलार्थी के पति के नाम खाता दर्ज है जिस खाता इन्द्राज के विरुद्ध आज तक रेस्पोजेन्ट/प्रतिवादी ने कहीं कोई भी आपत्ति दायर नहीं किया।

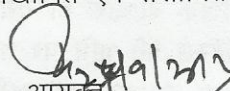
अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि उनके दो पुत्र कपिलदेव भार्मा एवं सकलदेव भार्मा है जो कि काफी सात्विक जीवन जीते हैं जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोजेन्ट/प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी के उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर अपीलार्थी को अपने पति से प्राप्त भूमि से बेदखल कर दिया गया है जिसके निदान हेतु अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दाखिल किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के साक्ष्य एवं सबूतों पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी के वाद को खारीज कर दिया गया।

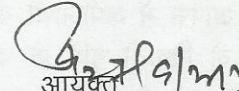
अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत विवादीत भूमि की निम्न न्यायालय द्वारा स्थलीय जॉच नहीं करवाई गई परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि " जमीन का पक्षकारों के बीच विवाद है जिस संबंध में सरपंच ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ष: 1990-91 से पॉचों भाई प्रश्नगत भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं सभी भाई का बराबर-बराबर हिस्सा है और तदनुसार वे दखलकार भी हैं। स्थलीय जॉच में भी पाया गया कि लम्बे समय से पॉचों भाई घर बनाकर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार हैं।" इस संदर्भ में निम्न न्यायालय का उक्त कथन असंगत एवं पक्षपातपूर्ण है।

अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी कथन किया गया है कि निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी के हक वो दखल के प्रमाण स्वरूप दाखिल कागजात पर कुछ भी विचार नहीं किया गया है और न ही निम्न न्यायालय द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा-5 का अनुपालन नहीं किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि इस मामले में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है, अतएवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है, तथा उभय पक्षों के संबंधित सभी तथ्यों, साक्ष्य, निबंधित दस्तावेज, जमाबंदी तथा स्थलीय जॉच के आधार पर समुचित आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा

  
आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा